जिनके तहत उत्तर प्रदेश में कताई तथा सूत मिलों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) बुनकर सहकारी कताई मिलों की अंश पूंजी में भाग लेने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सरकार नई हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से ऋण सहायता देती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम और आधुनिक बनाया जा सके। आठवीं योजना के दौरान 2 नई कताई मिलों को सहायता देने और 4 वर्तमान कताई मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में अब तक 2 लाख से भी अधिक तकले (स्पिन्डल) लगाये गये है।

जनता कपड़े के वितरण के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन न किया जाना

793. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता कपड़े के वितरण के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार को इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा सभी कार्यान्वयन राज्यों को जारी की गई व्यापक मार्गदर्शिका के आधार पर किया जाता है। इस मार्गदर्शिका के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण को अपने उत्पादन का कम से कम 85% उपभोक्ता सहकारी समितियों और लोक वितरण प्रणाली की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले इसी प्रकार के अभिकरणों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव/हथकरघा के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की कार्यान्वयन समितियों जिनमें नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, उपभोक्ता प्रतिनिधियों, अन्य विशेषज्ञों आदि को शामिल किया गया है, को अपने-अपने राज्यों में वितरण व्यवस्था की देख-रेख के कार्य सौंपे गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) तथापि विशेष शिकायतों के बारे में विशेष कार्यवाही की जाती है तथा दीर्घावधिक उपायों के रूप में मार्गदर्शिका के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

गुजरात में तकलों (स्पिंडलों) का वितरण

794. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय विकास निगमों के माध्यम से तकलों को वितरित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में कताई तथा सूत मिलों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) बुनकर सहकारी कताई मिलों की अंश पूंजी में भाग लेने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सरकार नई हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से ऋण सहायता देती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम् और आधुनिक बनाया जा सके। आठवीं योजना के दौरान 2 नई कताई मिलों को सहायता देने और 4 वर्तमान कताई मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। यह योजना गुजरात राज्य में भी लागू है।

New Policy to Development Wool Industry

795. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently evolved a broad policy framework to develop the wool industry; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The Industrial, Trade and Fiscal policies announced by the Government are mainly with a view to develop the Indian industries including woollen industry. So far as woollen industry is concerned, it has been exempted from compulsory

licensing and there are no restrictions in setting up of new units or expansion of the existing units subject to the locational guidelines evolved by the Government.

796. [Translated to 4th March, 1993]

राज्यों को जनता कपड़े की सप्लाई

797. **श्री गोपालसिंह जी, सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री 25 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 481 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता-कपड़े को सस्ती दरों पर बेचने के लिए प्रबन्ध किया है; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों को सप्लाई की गई जनता कपड़े की मात्रा उनकी मांग की तुलना में कम रही है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, वस्तुतः ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि उपभोक्ता अभिकरणों द्वारा जनता कपड़े की कम खरीद की गई है।

Sick Textile Mills in Gujarat

798. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 489 given in the Rajya Sabha on the 25th November, 1992 and state:

(a) what is the number of textile mills that are sick and closed in Gujarat;

(b) what are the reasons for their closure; and

(c) what steps have been taken for their rehabilitation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) As per information furnished by Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR), there were 50 Mills of Gujarat registered with BIFR as on 31.1.93. There were 34 closed textile mills in Gujarat as on 31.12.92.

(b) The financial difficulty is the main reason for closure of mills.

(c) Govt. have set up a Nodal Agency/ Board for Industrial and Financial Reconstruction to evolve and Manage Rehabilitation package in respect of sick/ closed textile Mills.

गुजरात में हथकरघा-विकास

799. **श्री गोपालसिंह जी सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात से हथकरघा के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों की मदवार संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में हथकरघा विकास के लिए वास्ताव में कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकट-स्वामी): (क) गत वर्षों के दौरान हथकरघों के आधुनिकीकरण, कार्यशाला-सह-आवास योजना, जनता कपड़ा योजना और विपणन विकास सहायता/विशेष छूट योजना आदि के संबंध में गुजरात राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य को हथकरघों के विकास के लिए जारी की गई राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि लाखों में
1989-90	641.38
1990-91	634.24
1991-92	141.84

Ban on Import of Raw Silk

800. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Indian raw silk Industry has come of age both in regard to quality and quantum of raw stock produced to sustain handloom and powerloom silk industry;

(b) if so, what are the reasons which prevent the Government to impose a ban on import of raw silk which has a destablising effect on domestic production; and

(c) whether Government would consider allowing incentive bases participation by the private Corporate sector on the lines of investment boom witnessed in the aqua culture projects all over the country considering its high export earning potential.